

### Hunger Strike by Central Government employees

\*122. SHRI MOHAMMAD ISMAIL:  
SHRI P. RAMAMURTI:  
SHRI SATYA NARAIN SINGH:  
SHRI K. M. ABRAHAM:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Government employees recently went on a hunger strike in the Capital to press their demands;

(b) if so, their demands; and

(c) the steps taken by Government to meet their demands?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). A few representatives of the Central Government Clerks' Union went on a hunger strike for 3 days with effect from 14th June, 1968 to press the following demands:—

- (i) Re-centralisation of Central Secretariat Clerical Service;
- (ii) Introduction of Selection Grade for L.D.Cs in the pay scale of Rs. 150—240;
- (iii) Stoppage of direct recruitment of Assistants;
- (iv) Automatic confirmation of temporary staff after they have served 5 years in a grade, and
- (v) Postponement of CSCS Upper Division Grade limited Departmental Examination till all L.D.Cs with 10 years service have been promoted as U.D.Cs.

The demands were carefully considered by Government but could not be accepted, as they stand. However, the possibility of making certain modifications to the present de-centralised administrative of the Central

Secretariat establishments from L.D. Clerk to S.O. is under examination.

MR. SPEAKER: Will you kindly answer Question No. 148 also? It is almost the same thing.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Yes, Sir.

### Joint Consultative Machinery of Government employees

\*148. SHRI S. K. TAPURLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the question of minimum wage, reducing the age of retirement to 55 years, full neutralisation of the increased cost of living and the merger of Dearness Allowance with pay in respect of Central Government employees have been under consideration of the Joint Consultative Machinery set up under the Ministry of Home Affairs; and

(b) the decisions, if any, taken on each of these issues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The question of minimum wage and that of merger of dearness allowance with pay in respect of Central Government employees was discussed in the meeting of National Council set up under the Joint Consultative Machinery. There is no proposal under consideration for reducing the age of retirement of Central Government employees to 55 years, and the question of its being discussed in the National Council does not arise. The question regarding full neutralisation of the increased cost of living was included in the Agenda for the meeting of the National Council held on the 12th July 1968. The matter, however, did not come up for discussion as the meeting of the National Council was adjourned.

(b) No final decision has been taken on the issues raised in the National Council.

**श्री मुहम्मद इस्माइल :** जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर विचार करने के लिए वह तैयार नहीं हैं। बेरा कहना यह है कि 20 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट कनकर्स यूनियन के लोगों ने बेराव का नोटिस दिया था तो चट्टान साहब उन से मिले थे और उन्होंने कहा था कि बेराव न करो, हम तुम्हारी डिमांड्स को मानेंगे क्योंकि इस में फाइनेंशियल लायबिलिटी इतनी अधिक नहीं आती है। इस के बाद उन्होंने कहा कि जी० सी० एम० से फिर मिलो और वहां न कुछ हो पाया तो हम तैयार हैं। तो मुझे यह पूछना है कि 19 तारीख को जो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया था कि हम से बात करेंगे और वह परसनली इंटरवीन करेंगे। तो उम पर प्रमल क्या किया है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस प्रश्न के ऊपर बहुत विस्तार से जो होम मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंटल कौंसिल है उस पर विचार किया गया और काफी इस बात का यत्न किया गया कि कोई समझौता हो सके। पर प्रफेसर्स की बात है कि किसी तरह का कोई समझौता इस में नहीं हो पाया और जैसा कि मैंने प्रपने मूल उत्तर में कहा हम लोग इस बात का यत्न कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता निकाल सके कि जिस से जो इन की डिमांड है डिसेंट्रलाइजेशन के अन्दर उस के ऊपर हम कुछ ऐसा कर सकें जैसे कि कोई जोन बना सकें प्रोमोशन के लिए, इन के ब्रेड के अन्दर, डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम के अन्दर ही जिससे कि इन की थोड़ी बहुत तकलीफ जो अर्नईन प्रोमोशन की है विभिन्न मंत्रालयों में इस का कुछ हल निकल सके क्योंकि यह हम लोगों ने सोचा कि विभिन्न सेवाएं जिनका बिकेन्द्रीकरण 1962 में किया गया था उन का फिर से केन्द्रीकरण कर दिया जाय तो फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है।

इसलिए बजाय उस का फिर से केन्द्रीकरण कर के वह नुकसान सहने के हम चाहते हैं कि जो बिकेन्द्रीकरण किया गया है उस को रखते हुए उस से जो थोड़ी बहुत मुश्किलें स्टाफ को हुई हैं उस का कोई रास्ता निकालें और उस के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री मुहम्मद इस्माइल :** 2 अगस्त को फिर वह उसी डिमांड पर जिस पर कि पहले वह गए थे और जिस पर हमारे होम मिनिस्टर ने उन से वायदा किया था, उसी को लेकर वह फिर उसी रास्ते में जाने वाले हैं तो मुझे यह पूछना है कि यह जो 60 परसेंट कन्फर्मेशन का मामला है जिस में कोई पैसा नहीं लगता है और जहां तक ब्रेड का मामला है जो प्रॉप ने कहा है कि हम कंसिडर करेंगे, इन तमाम बातों के लिए क्या 2 अगस्त से पहले होम मिनिस्टर उन से खुद मिलकर इस चीज को तय करने के लिए तैयार हैं या नहीं और 2 अगस्त को जो फिर नई घटना घटेगी उस की सारी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर होगी।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** गृह मंत्री उन से गिछले ही महीने मिल चुके हैं इस संबंध में और काफी बात भी हुई। हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किम तरह से इन की तकलीफें हम दूर करें। यह बात नहीं है कि हमें कोई सहानुभूति नहीं है या इन की तकलीफें हम दूर नहीं करना चाहते। पर तकलीफें दूर करने में हम यह नहीं चाहते कि कुछ तकलीफें दूर हों और दूसरी तकलीफें बढ़ जायं या और भी जटिलताएं पैदा हो जाएं। इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमारे एल०डी०सी० या क्लर्क यूनियन के लोग हैं उन को इस का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई कार्यवाही न करें जिससे कि स्थिति की जटिलता और बढ़े और किसी तरह से जो हम इस का हल ढूंढना चाहते हैं वह न उठ सके।

**श्री सत्यनारायण सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम कर्मचारियों में जो असन्तोष

फैल रहा है और इस के बारे में समय समय पर बात भी हुई तो इन की जो मांगें हैं सरकार उन को न्यायोचित समझती है या नहीं ? अगर उन की मांगें न्यायोचित हैं तो उन को मानने में और उस मसले को हल करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है और यह तो प्रश्न आपके सामने है उससे बहुत आगे की बात है, जनरल प्रिन्सिपल्स की बात है । इस के बारे में माननीय सदन को मालूम है कि हमारे यहां एक ज्वाइंट कन्सल्टेटिव मशीनरी बनी हुई है, उस की नेशनल काँसिल है और उस में इन प्रश्नों के ऊपर विचार हो रहा है । स्टाफ साइड के लोग और आफिशियल साइड के लोग मिल कर बात कर रहे हैं और हम लोगों का यत्न यह है कि इस के ऊपर कोई ऐसा हल बूँड सके जिस से कि इस में कोई समझौता हो सके और उन का प्रयत्न जारी है।

**SHRI K. M. ABRAHAM:** May I know from the hon. Minister whether the defence employees from all over the country went on a hunger strike before the residences of the Prime Minister and the Defence Minister? Did the Prime Minister receive the representatives of the defence employees and promise them that their grievances may be redressed? I came to understand that not only defence employees but all government employees are going on a strike on the 19th September and there may be a Bharat Bandh. Will the Government not consider this a serious matter, commence negotiations with the representatives of the union and settle the matter instead of precipitating it?

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:** As I said earlier, this is a larger question. We are making efforts to tackle this question and arrive at a settlement at different levels.

**SHRI S. K. TAPURIAH:** When an employee joins government service,

he joins with certain expectations. It is a sort of contract between the employee and the government. He knows in advance what are his conditions of service and what emoluments and other benefits he will get. So, at a later stage to go in for this sort of hunger strike is not proper. Those proposals which are before the JCM, if they are implemented, what would be the additional financial burden on the exchequer and how do the government propose to meet the burden? Secondly, will they provide the same sort of facilities for other workers in the country, the other wage-earners in the country who do not have the protection or security of government service?

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:** This is an important aspect of the question. But, unfortunately, I do not have the figures. If a separate question is asked, I will supply the figures.

**SHRI S. K. TAPURIAH:** What about the second part? Will the same facilities be provided to the working class in the private sector?

**SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:** That question is not before the government at present.

**श्री डा० ना० तिवारी :** सरकारी नौकरों में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम काम करते हैं। कुछ अधिक समय काम करते हैं और कुछ काम ही नहीं करना चाहते । कुछ आत्सी हैं और कुछ तेज हैं । क्या सरकार के सामने कोई ऐसा विचार है कि इन कर्मचारियों के काम का तखमीना हो कि वे कैसा काम करते हैं और बर्क के बेसिज पर उन को पे दिया जाय अधिक काम करने वाले को अधिक दी जाय और कम काम करने वाले को कम दी जाय ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इसके बारे में कई बार मुझाब सरकार के पास आये हैं और

में समझता हूँ कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उस के सामने यह प्रश्न विचार-धीन है। जब वे सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की मशीनरी के बारे में अपनी रिपोर्ट देंगे तब हम लोगों को उम्मीद है कि वे इस के बारे में कुछ कहेंगे और तब ही इस के बारे में सोच विचार किया जायगा।

**SHRI S. M. BANERJEE:** The question was whether the Central Government employees recently went on a hunger strike in the capital to press their demands. I am surprised that the Home Minister of this country does not know that there was another hunger strike by the leaders of the defence employees' union . . .

**MR. SPEAKER:** Evidently, there are so many such strikes in the country.

**SHRI S. M. BANERJEE:** . . . before the residences of the Prime Minister, Home Minister, Defence Minister and the Labour Minister of this country to meet their demands and the Prime Minister promised the delegation that she would speak to the Defence Minister about it. No mention has been made about it and I am not surprised. I want to know whether the Home Minister is aware, now that the JCM is dead and buried, because the Central Government have betrayed the employees by denying arbitration that the Central Government employees have decided yesterday to go on a token strike on the 19th September to be followed by a general strike if the government's attitude does not change. What steps have been taken to call a meeting at the national level—not the JCM, which is dead—to discuss the entire issue and fulfil the promises?

**THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN):** While the hon. Member may wish so, the position is that the JCM is not yet dead. It is very much alive and kicking.

**SHRI S. M. BANERJEE:** It is dead.

**SHRI MADHU LIMAYE:** It is at the moment kicking the employees.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** You may wish it to be dead but . . .

**SHRI S. M. BANERJEE:** Everyone in this country, including the INTUC has lost hope . . .

**SHRI Y. B. CHAVAN:** You are absolutely wrong. INTUC man is coming here. You may not know about it.

**SHRI S. M. BANERJEE:** There is a deadlock in the JCM. It has adjourned *sine die* and here is the Home Minister, making a statement misleading the House and confusing the country.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Here are persons who want to lead the country this way and ruin it. Unfortunately, you are misleading the Government employees also. I hope, they realise it. You are completely misleading them and are trying to use them for your political purposes which is absolutely wrong . . . (Interruption).

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** यह गलत-बयानी की है इन को ये शब्द वापस लेने चाहियें . . . (व्यवधान) . . . सियासी मकसद के लिये सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं—ऐसा इन्होंने कहा है—ये शब्द वापस होने चाहियें। अध्यक्ष महोदय, आप गृह मंत्री को कहिये कि वे ये शब्द वापस लें।

**SHRI S. M. BANERJEE:** Sir, I want your guidance. The fact of the case is that in the JCM they promised that there will be arbitration on this issue.

**श्री सु० प्र० शां :** अध्यक्ष महोदय . . .

**MR. SPEAKER:** I am glad, you have come. I thought, only Shri Sheo Narain was there. But now will you kindly sit down? I am on my legs and both of us cannot stand at one and the same time. If you want to ask a question, I will call you also.

श्री सु० प्र० शां : मुझे मत बुलाइये, उनको बान्स दीजिये, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिये ।

MR. SPEAKER: I will not allow this. You cannot start like this. I will give you a chance to ask a question and then you can say whatever you want to say now. I will give you a chance. I am glad that you have come and now it will be much more effective.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, my question was based on information which is a fact. At the Joint Consultative Machinery meeting the Government team headed by the Cabinet Secretary agreed that the question of minimum wage and of merger of dearness allowance were, according to the constitution of the JCM, arbitrable issues. A joint letter of intent was signed. In spite of that when a negotiated settlement could not be reached and the employees' representatives said unanimously, including the INTUC, that this should be referred to arbitration, they said that it was not arbitrable.

MR. SPEAKER: It is a debatable point.

SOME HON. MEMBERS rose—

श्री मधु लिमये : यह तो तथ्यों का सवाल है इस में विवादास्पद क्या है ।

MR. SPEAKER: Why do you want to get up when he is speaking?

श्री मधु लिमये : मैं उन को तार्हिद करने के लिये कह रहा हूं मुझे भी इसमें दिलचस्पी है ।

MR. SPEAKER: Is it parliamentary procedure? Does he need your help? He is capable of taking care of himself.

SHRI S. M. BANERJEE: I am only saying for the information of the House that my question was based on facts. The Home Minister, who is busy with other things, might not have gone through the papers and might not have read it; so, he says

that it is alive. It was adjourned *sine die* and all the representatives of the employees, including Shri A. P. Sharma, came out and said that strike was the only solution because the Government has gone back on it. Since there is a deadlock in the JCM and Government have not called a meeting of the JCM, the employees have refused to meet the Minister. I would like to know whether they are going to call a meeting at the national level. There is no politics; it is simply an economic demand of the Government employees.

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member is giving his argument. I do not want to give any argument. It is not the occasion for that.

SHRI S. M. JOSHI: Why do you call it politics? It is not politics.

SHRI Y. B. CHAVAN: The way you are trying to put it and interpret things, certainly I smell politics in it. Is Shri S. M. Joshi prepared to repeat what he said, namely, that the JCM is dead now? Is he prepared to say that?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप हज़ चीज़ में पोलिटिक्स देते हैं ।

श्री मधु लिमये : आप ने जे-सी-एम को खतम डाला है ।

श्री एस० एम० जोशी : आप पूछ रहे हैं तो मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, आप जवाब सुनिये ।

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not want politics to be brought into it.

MR. SPEAKER: Between you two you cannot arrange it. There is somebody else in the House to do it. Will you kindly sit down, Shri Joshi? Shri Vajpayee.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, the Home Minister was replying to my question.

**MR. SPEAKER:** I am not preventing him from answering the question. I do not mind hearing it if he has something to say.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** I am prepared to give all the information.

**MR. SPEAKER:** You have said that the committee is still alive.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Yes.

**MR. SPEAKER:** So, the only point is whether it is going to meet at some time.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Whether one certain meeting took place or not is not ultimately the test of the life of an organisation. There may be deadlock. But a deadlock does not mean that the body is completely dead. There may be difficulties also. I do not refute that. I would like to explain it. On this question, whether these two issues are arbitrable or not, there was disagreement about it. The Government felt that these issues, according to the constitution of the J.C.M., appeared to be non-arbitrable. This is the position. Now, the point is that they have taken a final position that they are arbitrable. We have made an offer through the Chairman of the National Council that three Ministers, the Deputy Prime Minister, the Home Minister and the Labour Minister, are prepared to meet their representatives to discuss these matters including whether this is arbitrable or not. (Interruption). That means they have made up their mind. (Interruption).

**MR. SPEAKER:** Order, order. You asked a question and he is replying. You must hear that.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** The Government's mind is open on this question as to whether this is arbitrable or not. First it appeared to us, from the interpretation of the constitution of the J.C.M., that they are non-arbitrable. We are prepared to discuss this matter with them. We have in-

vited them for talks. It is for them to accept or not.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अन्त्य महोदय, प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच में विवाद पैदा हो गया है तो क्या सरकार उस विवाद को हल करने के लिए अपना दिमाग खुला रखने को तैयार है ? एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि आपस में समझौता नहीं और विवादों को हल करने के लिये पंच फंसले को मामला सुपुर्ण कर दिया जाये क्योंकि कानून के अन्तर्गत भी इसकी व्यवस्था है और हुशारा संविधान भी इस बात का प्राविधान करता है कि अगर विवाद पैदा हो जाये तो पंच फंसले से उसको हल कर लिया जाये । मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के नेता आपसे बात करने का निमंत्रण स्वीकार कर लें लेकिन अगर बातों में कोई समझौता नहीं होता है तो क्या सरकार सारे मामले को पंच फंसले को सौंपने के लिए तैयार होगी ?

**SHRI Y. B. CHAVAN:** I do not want to give answers on hypothetical positions. I hope he gives them that advice and they accept that advice. If we reach that stage, certainly, you can ask those questions here and I am prepared to answer them. This is our approach. The J.C.M. also represents certain agreement between the Government and the staff side.

**SHRI S. M. BANERJEE:** It has been violated by the Government.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Whenever I try to explain to them, they do not want to understand. The J.C.M. agreement is also the result of certain negotiations between the Government and the staff side. Now, whenever there is dispute about the interpretation of that agreement, the only other course is to negotiate. Even the sovereign countries do not refuse to negotiate and meet. Here is an attitude of even refusing to meet. Is it reasonable?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जो बातचीत होगी अगर उसमें कोई समझौता नहीं हुआ तब क्या सरकार पंच फॉर्मले को मामला सीपेगी? क्या आविट्रेशन के बारे में सरकार का दिमाग खुला हुआ है?

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Why do you presume things? Let us argue this point also in the discussions. Why don't you discuss this issue also?

**SHRI S. M. BANERJEE:** We are prepared to discuss at national level.

**श्री चन्द्रजीत यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर बात है। पिछले दो वर्षों से हमारे देश के सरकारी कर्मचारी, चाहे वे राज्य सरकारों के हों या केन्द्रीय सरकार के हों, उनकी हड़तालें हो रही हैं जिससे सारे शासन का काम ठप्प हो जाता है और देश का नुकसान होता है। ऐसी स्थिति जो पैदा हो गई है वह देश के लिए बहुत गम्भीर है। अब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल की स्थिति भी पैदा हुई है। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ कि यह किसी दल विशेष का सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ के सारे कर्मचारियों ने हड़ताल की। विरोधी दल जो कि उस हड़ताल को कराने में प्रभुवा थे, जब उनकी सरकार बनी और वहाँ के राज्य कर्मचारी फिर हड़ताल करने लगे तो उनको नजरबन्दी वानून में रखा गया और उनको नौकरी से निकाला गया और उसका अभी कोई हल नहीं निकला है। मेरा कहना यह है कि कोई भी पार्टी शासन में आ सकती है लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति पैदा होगी और सरकार, कर्मचारियों का ऐसा रवैया रहेगा और उसका कोई हल नहीं निकाला जायेगा तो उससे सारे देश का बड़ा नुकसान होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और माननीय गृह मंत्री जी ने जो

आफर दिया है कि वे, उप प्रधान मंत्री और लेबर मिनिस्टर इन बात पर बात-चीत करने के लिए तैयार हैं, ताकि सरकारी कर्मचारियों को जा वाजिब मांगें हैं वह भी पूरी की जा सके और सरकार की जो कठिनाइयाँ हैं उनको भी ध्यान में रखा जा सके, क्या मैं इस बात की आशा करूँ कि कर्मचारियों के नेता भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुनः वार्तालाप करेंगे?

**SHRI Y. B. CHAVAN:** It is not for me to answer now.

**SHRI RANGA:** We are rather shocked to learn that the Central Government employees have refused to meet the Home Minister...

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Not even the Deputy Prime Minister.

**SHRI RANGA:** It makes it worse. It speaks of a very deplorable state of demoralisation of the Government as it is now manned by one party. Some time ago we had a strike by the policemen also. This morning my hon. friend, Mr. Vajpayee, raised a point and afterwards he has given it up fortunately. My hon. friend, the Home Minister, was attributing political motives to our friends. How is it that they have allowed the situation to reach such a state that politicians should exploit the Central Government employees as against the Government themselves, not only Government, but also the Home Minister, the Deputy Prime Minister and the Prime Minister. Does it speak well of the status and the prestige of this Government?

May I now put this question to the hon. Home Minister. He said they are prepared to discuss all questions, including whether this particular question is arbitrable or not—about J.C.M. Why not submit it to a judge of the Supreme Court to give his opinion whether it is arbitrable or not instead of themselves trying to scratch their heads and then ask them to come to a conference thereby giving

them an opportunity to defy the government, insult the government and the whole country. They are not prepared to meet the Home Minister!

SHI Y. B. CHAVAN: It is not a question of personal prestige . . . (Interruptions).

SHRI RANGA: The Upper Division Clerks and Lower Division Clerks do not have anything to do with him! What sort of Home Minister have we?

SHRI Y. B. CHAVAN: I have respect for an elderly person like . . . (Interruptions).

SHRI RANGA: The whole House, the whole country, feels insulted.

SHRI Y. B. CHAVAN: It is not a question of insult as such coming from any particular individual. They are speaking on behalf of government employees; they are a class; they are speaking as representatives in the JCM. It is not a question of an Under Secretary refusing to come and meet the Home Minister. He has to understand the difference between these two different propositions. It is not a question of that level. When a matter is raised whether we accept the principle that whenever there is a disagreement about interpretation of the agreement, every time we have to go for arbitration, it is a difficult position to accept.

SHRI K. N. PANDEY: May I know whether the dispute lies about the principle whether certain cases are arbitrable or not or some negotiations have been done on the merits of the case, and if that has been done, what is the difficulty of the Government to meet the demands of the employees?

SHRI Y. B. CHAVAN: I do not know why he is now speaking of Defence employees. As far as the JCM staff side is concerned, we have said that we are willing to meet them.

श्री कृष्ण लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, वनर्जी साहब का कहना है कि जो जे० सी० ए० म० का विधान है और जो करार हो गया है उसके अनुसार इन मांगों को पंचों के सामने भेजना चाहिए लेकिन इनका कहना यह है कि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। पहले तो सरकार ने कबूल किया था कि ऐसा हो सकता है लेकिन अब बाद में वे बदल गए। मेरा कहना यह है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना नहीं चाहते हैं तो इनकी नेशनल लेबर कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं उनकी राय मांगें कि यह आर्बिट्रेबिल है या नहीं। अगर वे यह राय देते हैं कि है, इस पर आर्बिट्रेशन हो सकता है तो फिर कोई झगड़ा नहीं रहे जायेगा और सरकार को उस राय को कबूल करना चाहिये। इस तरह से कम से कम झगड़े का एक कारण दूर हो जायेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर श्री गजेन्द्र गडकर की राय लेगी—जोकि नेशनल लेबर कमीशन के चेयरमैन है—कि यह आर्बिट्रेबिल है या नहीं?

SHRI Y. B. CHAVAN: I have answered this question.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDI: It is obvious that the representatives of the Government Employees are not satisfied with the offer made by the Home Minister to the representatives to come and meet a sub-committee. There is already a deadlock and they have already fixed a time to go on a general strike. In principle Government accept that matters of dispute like this should go for arbitration, if there is any constitutional difficulty in this particular matter, is it not proper to refer it to somebody who would advise on the constitutional aspects of it? I think that the matter is of such a serious nature that they should review the whole position and make it possible for the representatives to meet them so that the dispute could be referred to some authority who can take an impartial view of the whole matter.



**SHRI Y. B. CHAVAN:** We are willing to meet them. I have not refused to meet them. They are refusing to meet as representatives of the staff side.

**SHRI S. M. BANERJEE:** It is they who are refusing to meet the employees. We have already given the letters. I suggest, Sir, that you may allow a discussion, and we shall produce the documents.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** They have raised two demands, namely the merger on dearness allowance and the need-based minimum wage.

**AN HON. MEMBER:** Let the constitution of the JCM be placed on the Table of the House.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** According to the constitution of the JCM and the interpretation of the constitution of the JCM, Government feel that they appear to be non-arbitrable. This has been conveyed to them.

**SHRI RANGA:** Leave it to a Supreme Court judge.

**SHRI Y. B. CHAVAN:** But, at the same time, there is a convention that when things come to a difficult situation in the JCM, matters can be discussed with the Ministers because they are the representatives of Government as such. So, an offer was made that they could certainly come and discuss this matter, and it was also conveyed to them that even this question whether these are arbitrable or not could also be discussed and after discussion, all those suggestions including the suggestion made by some hon. Members including Shri Ranga can also be considered, and they can certainly put forward those arguments. This is Government's position and I think that it is a reasonable position.

**SHRI S. M. BANERJEE:** You may ask the hon. Minister to lay it on the Table of the House.

**SHRI P. VENKATASUBBAIAH:** No doubt, the Central Government employees have got the constitutional right to strike and to go on processions. But apart from this strike, may I know whether the Home Ministry is aware of the fact that when demonstrations of the Central Government employees are taken out, political slogans are raised and some of the slogans have denounced the Government of the day? May I know whether any political elements have been introduced into this, and whether this will not have a demoralising effect on the administration of the country? May I know whether this aspect of the matter has been gone into, and if so, what effective steps the Home Minister has taken so that these strikes and demonstrations may not take a political turn?

**SHRI Y. B. CHAVAN:** Naturally, any talk of strike of Government employees does have a rather demoralising effect on the administration, and it certainly affects adversely the interests of the country also in the last analysis. But as regards the exact slogans that were raised and by whom I have no confirmed information. I do not want to go into that matter at this stage.

**SHRI S. M. BANERJEE:** He has not heard them. How could he hear them from Parliament House?

**श्री अब्दुल गनी वार :** पाकिस्तान को इस से हथियार मिलने के बाद से खासतौर पर हिन्दुस्तान की स्थिति को ज्यादा ठीक व मजबूत बनाने के लिए ताकि वह आने वाले किसी भा खतरे का कामयाबी के साथ मुकाबला कर सके, क्या सरकार देश में यह जो इधर उधर लेकर अनरैस्ट हो रहा है या जगह जगह सरकारी और दूसरे मूलावलीन हड़तालें करते रहते हैं उन के मामलात को बातचीत करके सुलझाने के लिए जैसे कि उस ने वह नेशनल इंटिग्रेशन काँसिल बनाई उसी तरह से कोई एक गोलमेज वार्केंट बुलायेगी

जिसमें फ्रि कांफ्रेंस, अपोजीशन और लेबर के लीडर्स आपस में मिल कर और तबादला खयाल करके मामले को सुलझा लें और यह लेबर हड़तालें कम से कम एक मुद्दत तक के लिए मुलतवी करा दें ताकि देश एकजुट होकर कामयाबी के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सके ?

[ پاکستان کو روس سے ہتھیار ملنے کے بعد سے خاص طور پر ہندوستان کی استھتی کو زیادہ ٹھیک و مضبوط بنانے کے لئے تاکہ وہ آنے والے کسی بھی خطرے کا سامہابی کے ساتھ مقابلہ کر سکے - کہا سرکار دیہی مہن میں یہ جو اڈھر اڈھر لیبر انریسٹ ہو رہا ہے یا جکہہ جکہہ سرکاری اور دوسرے ملازمہن ہوتالہن کرتے رتتے ہوں ان کے معاملات کو بات چیت کر کے سلجھانے کے لئے جہسے کہ اس نے وہ نہشل انٹیکریشن کونسل بنائی اسی طرح سے کوئی ایک کولمہز کالگریس بلٹنگی جس مہن کہ کانگریس، ایوزیشن اور لیبر کے لیڈرس آپس مہن مل کر اور تہادلہ خہال کر کے معاملے کو سلجھا لوں اور یہ لیبر ہوتالہن کم از کم ایک مدت تک کے لئے ملتوی کرا دیں تاکہ دیہر ایک ہوکر یوری کامہابی کے ساتھ دشمن مقابلہ کر سکے - ]

SHRI Y. B. CHAVAN: At the present moment, there is no such proposal about this matter.

श्री शिव नारायण : क्या यह सत्य है कि सरकार के जो नीकर हैं उन के जो लीडर हैं

1150 (A) LSD—2.

वह लीडर उन को काम पर आने से रोक रहे हैं। गवर्नमेंट ने उन से बातचीत करने का जो प्रीफर किया है उसे मानने में कौन लोग बाधक हैं ? अगर उन के नाम मालूम हों तो मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करें ?

SHRI Y. B. CHAVAN: I have no information.

SHRI NAMBIAR: At the time of the negotiations which brought into existence the JCM, was it not made clear that certain items were to be sent for arbitration, and particularly the wages as well as dearness allowance which were the main points of dispute between the Central Government employees and the Government matters for reference to arbitration if there was no agreement between the two parties? This was one of the major decisions which was taken at the time of the setting up of the JCM between the representatives of the Government and the representatives of the employees, and, therefore, the question of interpretation does not arise, and there is no necessity for a discussion on that point which was already agreed upon.

SHRI Y. B. CHAVAN: The hon. Member is giving his interpretation, but I do not agree with it.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

\* 123. श्री श्रीकार सिंह :

श्री शारदा नन्ध :

श्री नारायण स्वल्प शर्मा :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह घोषणा की थी कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जो 21 वर्ष की सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहेंगे उन्हें, सेवा